



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07102020-222277
CG-MH-E-07102020-222277

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]	नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 6, 2020/ आश्विन 14, 1942
No. 411]	NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 6, 2020/ ASVINA 14, 1942

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 16 सितंबर, 2020

सं. टीएएमपी/11/2018-आईसीटीपीएल.— महापत्तन प्रशुल्क अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद् द्वारा इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (आईसीटीपीएल) में अप-तटीय कंटेनर टर्मिनल में आरओआरओ/स्टील/कंटेनर प्रचालन के लिए मौजूदा तदर्थ दरों की वैधता में विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/11/2018-आईसीटीपीएल

इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड. — आवेदक

गणपूर्ति

- (i). श्री टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii). श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(सितंबर, 2020 के 8 वें दिन पारित)

यह मामला इंदिरा कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट (आईसीटीपीएल) में अपतटीय कंटेनर टर्मिनल पर आरओआरओ/स्टील/कंटेनर प्रचालन के लिए मौजूदा तदर्थ दरों की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2.1 इस प्राधिकरण ने 24 जुलाई, 2019 के अपने आदेश के द्वारा मुंबई पोर्ट परिसर के भीतर विकसित अपतटीय कंटेनर टर्मिनल में आरओआरओ/स्टील/ कार्गो और कंटेनर प्रचालन के लिए प्रभारित की जाने वाली तदर्थ प्रशुल्क दरों की वैधता का विस्तार किया था। इस आदेश को भारत के राजपत्र में 21 अगस्त 2019 को राजपत्र संख्या 293 में अधिसूचित किया गया था।

2.2. 24 जुलाई 2019 के उक्त आदेश के द्वारा आईसीटीपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता का विस्तार 01 अप्रैल, 2019 के पूर्वप्रभाव से किया गया था यानी 31 मार्च, 2020 या आईसीटीपीएल के संदर्भ में पुनरुद्धार प्रक्रिया पूरी होने तक या अन्यथा, जो भी पहले हो। इस प्रकर आईसीटीपीएल में अपतटीय कंटेनर टर्मिनल पर आरओआरओ/स्टील/कंटेनर परिचालन के लिए मौजूदा तदर्थ दरों की वैधता 31 मार्च 2020 को पहले ही समाप्त हो चुकी है।

2.3 प्रसंगवश, यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आईसीटीपीएल के दरमान का निर्धारण पूर्व में प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2005 के तहत शासित था, जिसे अब भारत सरकार द्वारा जारी प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के तहत नियंत्रित किया जाएगा। प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के खंड 1.6 में निहित अनुबद्धता के अनुसार, वीओटी ऑपरेटर्स जिनके प्रशुल्क दिशानिर्देश 2005 के तहत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत दरमान मान्य हैं, वे इस दौरान इन दिशानिर्देशों के तहत अपने दरमान की समीक्षा के लिए एक प्रस्ताव दाखिल कर सकते हैं या मौजूदा दरमान के लागू रहने या मौजूदा दरमान की वैधता की समाप्ति के बाद। इस प्रकार, आईसीटीपीएल को प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के अनुसार अपनी दरों में सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल करने की आवश्यकता है, क्योंकि 2005 के दिशानिर्देशों के तहत इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मौजूदा दरमानों की वैधता 31 मार्च 2020 को समाप्त हो गई है।

3. इस पृष्ठभूमि में, आईसीटीपीएल ने अपने पत्र क्रमांक ओपीएस/टीओपी/ टीएएमपी/एल/1/ 20-21 दिनांक 13 जून 2020 में उल्लेख किया है कि परियोजना के पुनरोद्धार की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इस प्राधिकरण से दरमानों की मौजूदा वैधता 6 महीने की एक और अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

4. इस मामले पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ आईसीटीपीएल के दिनांक 13 जून, 2020 के पत्र की एक प्रति लाइसेंस प्रदाता पत्तन मुंबई पत्तन न्यास (एमबीपीटी) को भेजी गई। इसके जवाब में, एमबीपीटी ने अपने पत्र क्रमांक एफए/एसीसी/254-II/1459 दिनांक 10 जुलाई 2020 के अंतर्गत उल्लेख किया है कि एमबीपीटी को आईसीटीपीएल के मौजूदा दरमानों को 01 अप्रैल, 2020 से 6 महीने के लिए विस्तार करने पर या जब तक आईसीटीपीएल द्वारा कोई नया प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया जाता, जो भी पहले हो, पर कोई आपत्ति नहीं है और यह भी कि प्राधिकरण को आदेश 01.04.2020 के पूर्वव्यापी प्रभाव से जारी करना होगा।

5.1. एमबीपीटी और आईसीटीपीएल ने एक ऐसी व्यवस्था के लिए सहमति हैं जिससे एमबीपीटीएल द्वारा आईसीटीपीएल को पुनरुद्धार प्रक्रिया पूरी होने तक कंटेनर सहित प्रशुल्क स्तर पर घाटभाड़ा एमबीपीटी के लिए अनुमोदित दरमानों में निर्धारित बर्थ भाड़े का 1.3 गुना अन्य कार्गो मर्चों के लिए आईसीटीपीएल को अनुमति देगा। इस व्यवस्था को इस प्राधिकरण द्वारा स्वीकार कर लिया गया है और आईसीटीपीएल को 31 जुलाई 2018 को प्रशुल्क आदेश के तहत लागत की स्थिति का विश्लेषण करने के बाद तदर्थ दरें उगाहने की अनुमति दे दी गई है।

5.2 इस बात पर सुविचार करते हुए कि परियोजना के पुनरुद्धार की प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है और इस बात पर भी सुविचार करते हुए कि एमबीपीटी को आईसीटीपीएल के मौजूदा दरमानों का विस्तार करने में कोई आपत्ति नहीं है और कि प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए दरमानों की मौजूदा वैधता को 31 मार्च, 2020 से आगे विस्तार करना उचित समझा जाता है।

5.3 लेकिन, चूंकि अब सितंबर, 2020 है, 01 अप्रैल 2020 से आगे 30 सितंबर, 2020 तक 6 महीने की अवधि के लिए विस्तार की स्वीकृति देना, आईसीटीपीएल द्वारा यथाप्रस्तावित, बहुत छोटी अवधि है। यह बताया गया है कि परियोजना की अभी समीक्षा की जानी है और प्रशुल्क दिशानिर्देश 2019 के अंतर्गत आईसीटीपीएल के परियोजना के पुनरुद्धार के आधार पर आईसीटीपीएल द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव की संक्रिया में लगने वाले समय को ध्यान में रखकर और प्रशुल्क में निर्वात से बचने के लिए, यह उपयुक्त समझा जाता है कि आईसीटीपीएल के मौजूदा तदर्थ प्रशुल्क की वैधता अवधि में 31 मार्च 2020 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 01 अप्रैल 2020 से 31 मार्च, 2021 तक या आईसीटीपीएल द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित नई दरों के लागू होने तक या परियोजना के पुनरुद्धार के समय तक या अन्यथा जो भी पहले हो, विस्तार किया जाये।

6.1 इस प्रकार, पूर्ववर्ती पैराओं में दिए गए कारणों के आधार पर और समग्र सोच-विचार के आधार पर, यह प्राधिकरण, (प्रशुल्क में उत्पन्न शून्यता से बचने के लिए और एमबीपीटी के अनुरोध पर), आईसीटीपीएल के मौजूदा दरमानों की वैधता में 01 अप्रैल 2020 से एक वर्ष की अवधि के लिए यानी 31 मार्च 2021 तक या जब तक कि आईसीटीपीएल के संबंध में पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, या अन्यथा, जो भी पहले हो, पूर्वव्यापी प्रभाव से विस्तार करता है।

6.2 इस मध्यवर्ती अवधि के दौरान, जब तक पुनरुद्धार की प्रक्रिया पूरी होती है, आईसीटीपीएल को, वर्तमान में आईसीटीपीएल के संबंध में लागू प्रशुल्क के संबंध में प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2019 के आधार पर अपना प्रस्ताव दायर करना चाहिए।

6.3 आईसीटीपीएल यह नोट करे कि यदि 01 अप्रैल 2020 के बाद की अवधि के लिए निष्पादन की समीक्षा के दौरान ग्राह्य लागत और अनुज्ञेय प्रतिफल के अतिरिक्त अधिशेष पाया जाता है तो ऐसे अधिशेष को निर्धारित किये जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समावेशन किया जायेगा।

7. यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एमबीपीटी के मौजूदा दरमानों में इस प्राधिकरण ने 24 जुलाई, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/5/2019-एमबीपीटी द्वारा संशोधित कर दिया है, जो 03 अक्तूबर, 2019 से प्रभावी किये गये हैं। क्योंकि, आईसीटीपीएल को, एमबीपीटी पर लागू होने वाली घाट दरों को लागू करने और एमबीपीटी के बर्थ किराया शुल्क के 1.3 गुना पर बर्थ किराया शुल्क लगाने के लिए अधिकृत किया गया है, अतः, एमबीपीटी में तत्समय लागू एमबीपीटी के संशोधित दरमान, जैसा कि एमबीपीटी ने सहमति व्यक्त की है, आईसीटीपीएल के लिए भी लागू होंगे।

टी. एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./272/2020-21]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**NOTIFICATION**

Mumbai, 16 September, 2020

No. TAMP/11/2018-ICTPL.— In exercise of the powers conferred by Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the existing adhoc scale of rates for RORO / Steel / Container Operations at Offshore Container terminal at Indira Container Terminal Private Limited (ICTPL), as in the order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**Case No. TAMP/11/2018-ICTPL****Indira Container Terminal Private Limited**

- - -

Applicant**QUORUM**

- (i). Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii). Shri. Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 8th day of September 2020)

This case deals with the extension of the validity of the existing adhoc scale of rates for RORO / Steel / Container Operations at Offshore Container terminal at Indira Container Terminal Private Limited (ICTPL).

2.1 This Authority vide its Order dated 24 July 2019 had extended the validity of the existing adhoc tariff rates of ICTPL to be charged for RORO / Steel / Cargo and Container Operations at Offshore Container Terminal developed within the Mumbai Port Premises. This Order was notified in the Gazette of India on 21 August 2019 vide Gazette No.293.

2.2. Vide the said Order dated 24 July 2019, the validity of existing SOR of ICTPL was approved retrospectively from 01 April 2019 for a period of one year i.e. upto 31 March 2020 or till the revival process is completed in respect of ICTPL, or otherwise, whichever is earlier. As such, the validity of the existing adhoc scale of rates for RORO / Steel / Container Operations at Offshore Container terminal at ICTPL has already expired on 31 March 2020.

2.3. It is relevant here to state that the fixation of SOR of ICTPL was previously governed under the Tariff Guidelines, 2005 which will be now governed under the Tariff Guidelines, 2019 issued by the Government of India. As per the stipulation contained at clause 1.6 of the Tariff Guidelines, 2019, the BOT Operators whose Scale of Rates (SOR) approved by this Authority under the Tariff Guidelines 2005 are valid may, either file a proposal for review of their SOR under this Guidelines during the currency of the existing SOR or, after expiry of the validity of the existing SOR. As such, the ICTPL is required to file proposal for general revision of its scale of rates as per the Tariff Guidelines, 2019, as the validity of the existing SOR approved by this Authority under 2005 guidelines has expired on 31 March 2020.

3. In this backdrop, the ICTPL vide its letter OPS/TOP/TAMP/L/ 1/20-21 dated 13 June 2020 has stated that project revival process is not yet completed and has requested this Authority to extend the validity of the existing scale of rates for another period of 6 months.

4. A copy of the ICTPL's communication dated 13 June 2020 was forwarded to the Licensor Port Mumbai Port Trust (MBPT) for its comments on this matter. In response, the MBPT vide its letter No. FA/ACC/254-II/1459 dated 10 July 2020 has conveyed that the MBPT does not have any objection for extension of existing SOR of ICTPL for further period of six months from 01 April 2020 or new proposal is submitted by ICTPL whichever is earlier and that TAMP may also like to issue the order retrospectively from 01.04.2020.

5.1. The MBPT and the ICTPL have agreed for an arrangement whereby MBPT will permit ICTPL to handle other cargo items including container at the tariff level approved for MBPT for wharfage and 1.3 times of berth hire prescribed in the SOR of MBPT till the revival process is completed. This arrangement has been accepted by this Authority and the ICTPL has been permitted to levy the rates on adhoc basis after analysing the cost position vide tariff order dated 31 July 2018.

5.2. Considering that the project is yet to be revived and also considering that MBPT has conveyed its no objection for extension of validity of existing SOR and in order to avoid a vacuum in tariff, it is felt appropriate to continue adhoc tariff arrangement by extending the validity of existing adhoc SOR of ICTPL beyond 31 March 2020.

5.3 However, since it is September 2020 now, granting extension for a period of six months beyond 01 April 2020 upto 30 September 2020, as proposed by ICTPL, is felt to be too short a period. Given that project is yet to be reviewed and considering the time required for processing the proposal to be filed by the ICTPL based on the revival of the project of ICTPL under Tariff Guidelines, 2019 and in order to avoid a vacuum in the tariff, it is felt appropriate to extend the validity of the existing adhoc tariff of ICTPL beyond 31 March 2020 for a further period of one year i.e. from 01 April 2020 to 31 March 2021 or till new rates are approved by this Authority based on the proposal (to be) filed by ICTPL or till the time the project is revived, or otherwise, whichever is earlier.

6.1. Thus, based on the reasons as brought out in the preceding paragraphs and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of existing SOR of ICTPL retrospectively from 01 April 2020 (so as to avoid vacuum in tariff and as requested by MBPT) for a period of one year i.e. upto 31 March 2021 or till new rates are approved by this Authority based on the proposal (to be) filed by ICTPL or till the revival process is completed in respect of ICTPL, or otherwise whichever is earlier.

6.2. In the intervening period, as and when the revival process is completed, the ICTPL should file its proposal for fixation of its tariff based on the Tariff Guidelines, 2019, which is now applicable in respect of ICTPL.

6.3. The ICTPL may note that if any additional surplus over and above the admissible cost and permissible return emerges for the period post 01 April 2019, during the review of its performance, such additional surplus will be set off fully in the tariff to be determined.

7 It is relevant to mention here that the Scale of Rates of MBPT was revised vide TAMP Order No. TAMP/5/2019-MBPT dated 24 July 2019 which is effective from 03 October 2019. Since the ICTPL has been authorised by MBPT to levy wharfage rates as applicable to MBPT and to levy berth hire charges at 1.3 times of the MBPT berth hire charges, the revision in the SOR of MBPT vide the above referred order shall also apply to the ICTPL.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty/272/2020-21]